

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला: यह बड़े अफसोस की बात है कि महिला बिल(व्यवधान)....

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, there is an intriguing silence on the part of the Government and the Prime Minister. (Interruptions).

श्री संजय निरूपम: मैं आप लोगों की सपोर्ट में खड़ा हूँ। लेकिन क्वेश्चन आकर के बाद अगर इस विषय पर बातचीत की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।(व्यवधान)....

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Let the Prime Minister say something. (Interruptions).

श्री संजय निरूपम: मेरे ख्याल से प्रश्न काल के बाद जीरो आकर में इस पर बात हो तो ज्यादा अच्छा होगा। कम से कम प्रश्न काल को इस तरह बाधित न किया जाए।

डा० (श्रीमती नाजमा हेपतुल्ला): महिलाओं के लिए वहाँ भी लोगों को खड़े होना चाहिए।(व्यवधान)....

श्री संजय निरूपम: हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग इसके अगेस्ट नहीं हैं।(व्यवधान)....

MR. CHAIRMAN: The Prime Minister has agreed.

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): सभापति जी, सरकार महिलाओं के आरक्षण विधेयक को लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आशा करते हैं कि वह बिल सर्वसम्मति से पास होगा। उस विधेयक को प्रस्तुत करने का फैसला कर लिया गया था। लेकिन एक दल के कुछ सदस्यों ने कहा कि उसके कुछ प्रावधानों पर फिर से विचार होना चाहिए। सर्वसम्मति बनाने के लिए यह तय हुआ कि एक सर्वदलीय बैठक फिर से आयोजित की जाए और उसमें अगर संभव हो तो सब की राय से विधेयक को पेश करने का फैसला किया जाए। वह बैठक आयोजित होने जा रही है। उसमें सर्वसम्मति बनाने का प्रयास होगा। मैं आशा करता हूँ कि सर्वसम्मति बनेगी। लेकिन, जहाँ तक, हमारा प्रश्न है और मैं देख रहा हूँ कि अन्य सदस्यों की भी जहाँ तक राय है, वह राय यह बन रही है कि अगर सहमति न भी हुई तो भी विधेयक को विचार के लिए प्रस्तुत कर दिया जाए और हम ऐसा ही करने जा रहे हैं।

श्रीमती कमला सिन्हा: सभापति महोदय, केवल विचार के लिए नहीं। हम यह चाहते हैं कि विचार करने के साथ साथ इसको पारित करने के लिए आप लायें। इसमें आपका भी कमिटमेंट है।

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Piling up of Steel at SAIL

*281 SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) Whether a large quantity of steel is piling up at SAIL for the last few months;

(b) if so, the quantity lying at each plant/stockyard; and

(c) the steps being taken by Government to ensure that these stocks of steel are delivered to the steel users at the earliest?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI NAVEEN PATNAIK):

(a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) During the first three months of the current financial year, stocks at plants and stockyards system of Steel Authority of India Limited (SAIL) have been brought down. The total quantity of Saleable Steel (Mild Steel), lying in the four Integrated Steel Plants and the Stockyards, as on 01/07/1998, was approximately 1.14 million tonnes as against approximately 1.23 million tonnes (provisional) on 01/04/1998.

(c) Some of the steps being taken by SAIL to increase sales and reduce stocks, inter-alia, include fine-tuning the product-mix in terms of market requirement; entering into MOUs with customers for regular supplies during the year; adopting market driven pricing strategies; entering into supply arrangements through participation in tenders/negotiations with various customers including projects, Government Departments, PSUs, Railways, etc.; increasing the despatch directly to customers etc.

श्री संजय निरूपमः सर, स्टील की इन्वेस्टन्डी का जो प्रश्न है वह बहुत पुराना है और यह बहुत गंभीर प्रश्न है। पिछले तीन-चार सालों से लगातार स्टील के अलग अलग जो एंटीप्रोटेड प्लॉट है, जैसे बोकारो है या भिलाई है, इन प्लॉटों में स्टील का स्टॉक लगातार बढ़ता जा रहा है। तकरीबन डेढ़ मिलियन या पौने दो मिलियन तक यह पहुंच गया है और इसी के आधार पर मैंने यह सवाल किया था। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह एक अच्छी खुशखबरी देकर दिया गया जवाब है कि पिछले तीन महीनों में इन्वेन्ट्री कम हुई। अभी तक ऐसी खबर थी कि सेल की इन्वेन्ट्री बढ़ रही है और सेल का प्रॉफिट घटता चला जा रहा है और स्टॉक क्लियरेंस करने के लिए स्टॉक क्लियरेंस के नाम पर बहुत सारा स्टील रिबेट पर डिसकाउंट पर दिया जा रहा है और बहुत हद तक ऐसा किया जा रहा है। अनसिक्योरिटी क्रेडिट के नाम पर एक हजार करोड़ रुपए का स्टील मार्केट में फेंक दिया गया है। वगैर किसी सिक्यूरिटी के क्रेडिट पर तकरीबन 700 से एक हजार करोड़ के बीच का स्टील मार्केट में यो ही फेंक दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि वगैर सिक्यूरिटी के, वगैर प्रॉपर सिक्यूरिटी के जो स्टील मार्केट में दिया जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेचा जा रहा है, यह क्या अच्छी बात है और जो अनसिक्यूरिटी क्रेडिट है जो एक हजार करोड़ के आसपास है तो उस क्रेडिट को वापस लेने का क्या प्रावधान है? सेसिफिकली क्वेश्चन मेरा यह है कि आखिर किस रेट पर स्टील बेचा जा रहा है? क्या वह जो मार्केट में स्टील का रेट है उससे कितने कम परसेंट पर बेचा जा रहा है? मैं मंत्री महोदय से विशेषतौर से यह जानना चाहता हूँ कि किस रेट पर स्टील बेचा जा रहा है और कितना समझौता इसमें किया जा रहा है, कितना कम्प्रोमाइज किया जा रहा है?

SHRI NAVEEN PATNAIK: Sir, in reply to the hon. Member's question, I would say that there is credit to the extent of Rs. 800 crores. The method of this is that while extending unsecured credit, there is an internal mechanism for assessing the credit-worthiness of parties. however, there is no assessment of credit-worthiness of parties carried out through an outside agency.

श्री संजय निरूपमः मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह कौन सी कम्पनी हैं जिनको अनसिक्यूरिटी क्रेडिट के आधार पर स्टील दिया गया है? मेरे पहले सप्लीमेंटरी का मुद्दा यही है।

SHRI NAVEEN PATNAIK: Sir, steel is being sold at market rates. There is a Committee of Directors in the Steel Authority of India Limited which, on a monthly basis, decides what the market rate has to be. Sir, the SAIL which is the major steel manufacturer has also got competition from other parties. So we have the Committee of Directors of the Steel Authority of India Limited and this Committee consists of Commercial Director, Finance Director and Chairmen and Managing Directors of the four integrated steel plants, namely, Rourkela, Bhilai, Bokaro and Durgapur.

श्री संजय निरूपमः मेरे इस सवाल का जवाब तो नहीं आया लेकिन मैं दूसरा सप्लीमेंटरी पूछता हूँ। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीमः यह तो तीसरा होगा (व्यवधान)

श्री संजय निरूपमः नहीं नहीं, मैंने दूसरा अभी नहीं पूछा है। जितनी इन्वेन्ट्री बढ़ती जाती है लॉस उतना बढ़ता चला जाता है और प्रॉफिट कम होता चला जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि जब स्टील सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जा रहा था, उस समय सेल का प्रॉफिट 1991-92 में 367 करोड़ था। उसके बाद जैसे ही प्राइवेटाइजेशन होता है 1995-96 में यह प्रॉफिट 1319 करोड़ हो जाता है। उसके बाद 1996-97 में एकदम 50 परसेंट प्रॉफिट हो जाता है और यह फिगर है 588 करोड़ इसके एक साल बाद 1997-98 में प्रॉफिट 116 करोड़ रह जाता है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि सेल का जो प्रॉफिट लगातार गिरता चला जा रहा है, क्या इस ओर उनका ध्यान है? सिर्फ स्टॉक क्लियरेंस या इन्वेन्ट्री कम कर देने से बात नहीं बनने वाली है। मेरा जो पहले सप्लीमेंटरी मैं शक था, वह यह है कि लोअर प्राइस पर अनसेसरी डिसकाउंट पर, अनसिक्यूरिटी क्रेडिट पर स्टील को मार्केट में फेंका जा रहा है, इससे लगातार सेल का प्रॉफिट घटता जा रहा है। मुझे डर है कि एक ही साल में सेल लॉस में जा सकता है।

SHRI NAVEEN PATNAIK: Sir, as I mentioned earlier, I am repeating for the hon. Member that we have a Committee of Directors which, on a monthly basis, processes the price of Regarding reasons for the pile-up steel in the stockyards of SAIL as well as the four integrated steel

plants, there has been an improvement in the situation because on the 1st of April, this year, we had a stock of 1.23 million tonnes of saleable steel materials, but on the 1st of July, that is, on the 1st of this month, it has come down to 1.14 million tonnes, which is less than what it was on the 1st of April. The reasons for this...

श्री संजय निरूपम: यह जवाब हमें मिल चुका है, रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। (व्यवधान)

SHRI NAVEEN PATNAIK: I would request the hon. Member to repeat his question

श्री संजय निरूपम: मेरा कहना यह है कि लगातार प्रॉफिट गिरता जा रहा है, इसका क्या कारण है? क्या इसकी इन्क्वायरी सेट-अप की जा सकती है? लगातार जो प्रॉफिट सेल का घटता जा रहा है, क्या इस ओर मंत्री महोदय ने गम्भीरता से ध्यान दिया है, छानबीन या इन्क्वायरी की जा रही है?

SHRI NAVEEN PATNAIK: I again repeat that we, on a monthly basis, review the sales. So far as enquiry is concerned, if an enquiry is required, of course, we shall look into the matter.

MR CHAIRMAN: The Minister has not properly answered the question. Probably he does not have the information.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Through you, Sir, I would like to put this question to the hon. Minister. He knows very well that the economy of any country depends upon core sectors. And steel is the major sector. Steel is being accumulated in steel plants, whether they are public or private. I would like to know what the Minister plans to do when MNCs from all over the world are dumping steel in the country. What are his plans to save this industry? This Government is talking about saving the Indian industry whereas what we are seeing is that steel production is going down and the stock is going up. There has been a reduction of stock of 90,000 tonnes only in one steel plant. My friend has already mentioned under what circumstances that has happened. Is it going to strengthen

the core sector, the steel industry? This is what I would like to know from the hon. Minister.

SHRI NAVEEN PATNAIK: Sir, the Ministry of Steel has made it clear to SAIL that its performance has to improve in the coming months. We have asked them to take the following actions in particular; prepare a time-bound action plan for turn-around of Rourkela and Durgapur steel plants, which will be closely monitored by the Ministry; undertake comprehensive cost-reduction exercises for improvements in techno-economic implementation; undertake Voluntary Retirement Scheme and shed non-essential and non-core activities, etc.; devise more aggressive marketing strategies, both for domestic sales as well as for exports; target new areas of customers in order to attain a larger market share, and, improve the quality of their products so as to compete with other producers in the private sector.

श्री रामदास अग्रवाल: सभापति महोदय, जैसा कि अभी मेरे सहयोगी ने बताया कि स्टील इंडस्ट्री ने पहले 1319 करोड़ रुपये तक का प्रॉफिट अर्जित किया था, लेकिन अब धीरे-धीरे इसकी प्रॉफिटैबिलिटी कम होती जा रही है। उसके कई कारण हैं। उसमें से एक एक्सपेंशन है। उसी से संबंधित मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो एक्सपेंशन हो रहे हैं स्टील प्लांट्स के, आपके पहले के प्रोडक्शन के आधार पर बितना सेल होता था उतना भी आप सेल, नहीं कर पाए। तब एक्सपेंशन में जो आपने 10 हजार करोड़ रुपया खर्च किया है और वह अब लगभग पूरा हो चुका है, तो उसका जो प्रोडक्शन होगा क्या आप उसको भी मार्केट में बेच पायेंगे? दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इंपोर्ट जो स्टील हिन्दुस्तान में इंपोर्ट किया गया है मल्टी नेशनल कंपनियों के माध्यम से तो उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के बारे में क्या सरकार ने विचार किया है?

SHRI NAVEEN PATNAIK: Sir, according to the recent Budget, there has been a price hike in the import of steel products. With the hike in the import duty, it is more expensive now to import steel. Therefore, that works...

श्री रामदास अग्रवाल: सर, मैं तो यह पूछ था कि एक्सपेंशन के बाद सेल की क्या स्थिति बनेगी?

MR. CHAIRMAN: Please. This is a very serious question. A number of interventions may be required. The Minister is not well-prepared. I may suggest that we should have a Half-an-Hour Discussion, when both the Minister and the Members come well-prepared. Somebody has to give notice and we shall decide.

Rate of Interest on the Corpus of Family Pension

*282 SHRI C.O. POULOSE:
SHRI JIBON ROY:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Standing Labour Committee has recommended enhancement of rate of interest on the corpus of family pension;

(b) if so, the details of the recommendations; and

(c) the steps taken by Government on these recommendations?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) Yes Sir.

(b) and (c) The Standing Labour Committee (SLC) of the Indian labour Conference had recommended that the Pension fund and the Employees Deposited-Linked Insurance Fund deposited in the Public Account should receive interest of not less than 12.5 percent as compared to the present return of 8.5 percent. The matter has been considered in consultation with the Ministry of finance. However, it has not been found possible to accept the proposal.

SHRI C.O. POULOSE: Sir, my first supplementary is this: The Employees' Pension Scheme was made effective from 1995. The amount of Family Pension Fund was credited to the Employees' Pension Fund from the same date. The Government has not allowed interest rate

as recommended by the Standing Labour Committee. This amount is huge. It is more than ten thousand crores of rupees. Will the Minister please disclose the amount that the Pension Fund lost by a higher interest rate not being granted, as recommended by the Standing Labour Committee from the date of merging of this Fund with the Employees' Pension Fund?

डा० सत्यनारायण जटिया: माननीय सभापति जी, यह प्रश्न वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है किंतु पेंशन के संदर्भ में जो नीतिगत मामला है, उस बारे में प्रश्नकर्ता जानते-होंगे कि सन् 1971 से यह पेंशन स्कीम प्रारंभ हुई। इस पेंशन स्कीम में 1.16 परसेंट के हिसाब से कंटीब्यूशन होता था और यह कामगार, प्रबंधन और सरकार का ट्राइपाट्रिट कंटीब्यूशन हुआ था। इस प्रकार इस स्कीम का प्रारंभ हुआ और उस वक्त इस पेंशन स्कीम का लाभ काम करते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु होने के उपरांत मिलता था। बाद में इस पेंशन स्कीम में संशोधन होता गया। यह भी पूछा गया कि इस पेंशन स्कीम के कारण एकुमुलेशन हो गया है और वह राशि बहुत बढ़ गयी है इसलिए इस बढ़ी हुई राशि पर इंटेरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाना चाहिए जिससे कि उसका दायरा बढ़ सके।

सभापति जी, निश्चित रूप से प्रश्नकर्ता जानते होंगे कि यह जो स्कीम है, इस में सरकार का 1.16 परसेंट कंटीब्यूशन आता है। बाद के समय में इस कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी के एम्प्लायर्स का शेयर 8.5 परसेंट इस पेंशन स्कीम के कंटीब्यूशन में जाता है। सभापति जी, जब यह नई पेंशन स्कीम बन रही थी तो उस पेंशन स्कीम में सभी ट्रेड यूनियंस का आग्रह था कि 1.16 परसेंट जो सरकार की ओर से कंटीब्यूशन जा रहा है, इस पर भी रेट ऑफ इंटेरेस्ट बढ़ाया जाय और चूंकि इस पेंशन स्कीम के सन् 1971 से लागू होने के बाद 1.16 परसेंट सरकार का पैसा उस में जाता है और जो सरकार का कंटीब्यूशन है उसी पर क्योंकि 8.5 परसेंट इंटेरेस्ट मिल रहा है अब इस पर भी यह अपेक्षा की जा रही है कि 12 परसेंट से अधिक इंटेरेस्ट मिले। इस प्रश्न पर वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा और विचार-विमर्श किया जा रहा है, किंतु उन का यह कहना है कि अभी तक इस बारे में कोई स्वीकारोक्ति नहीं मिली है, इसी कारण यह नहीं हुआ है।

सभापति जी, चूंकि आई० एल० सी० में भी यह इस प्रकार से मंजूर हुआ था और श्रम मंत्रालय ने इसे

The question was actually asked on the floor of the house by Shri C.O. Poulouse.